ने ऐसे ग्रादिमयों को वहां भर्ती किया है जिसका कि कांग्रेस पार्टी से सम्बन्ध रहा है भौर ग्राज भी जब दिल्ली प्रशासन एन्द्रवायरी करने जाता है तो मन्त्री महोदय ग्रीर स्टेट मिनिस्टर को होम मिनिस्ट्री में है वह हस्तक्षेप करते हैं? उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए वह तैयार नहीं है। तो मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि क्या वह न्यायिक जांब इसमें करकाएंगे ग्रीर होम मिनिस्टर से कहेंगे कि वह इसमें हस्तक्षेप न करें?

एक माननीय सवस्य : दिल्ली प्रशासन को बचाने के लिए यह सवाल किया है।

भी घटल विहारी कालवेथी: हां, जरूर बचायेंगे, वह हमारा प्रशासन है।

श्री राम स्वरूप विकार्षी: श्रष्टगक्ष महोदय जवाब भाना चाहिए। यह मेरी परसनल नालेज में है कि स्टेट मिनिस्टर साहब इसमें हस्तक्षेप करते हैं...

श्रध्यक्ष महोदय: श्रापके मात्रजर्वेशंग रैकर्ड पर मा गण, मन मोर क्या चाडिए ?

श्री ग्रटल बिहारी बाजवेगी : नहीं ग्रध्यक्ष महोदय, एक सवाल कुण गया है, उसका जवाब ग्राना चादिए, क्या यह सच है कि इन संस्थाओं में जिन कर्कवारियों की नियुत्ति की गई है यह 1967 के पहले की गई है, यह सच है या नहीं. यह उन्हें बताना चाहिए।

श्राच्यक्ष महोदय: श्रगर ऐसा सवाल होता तो में जरूर जवाब दिववा देता। मन्त्री महोदय इसका जवाब देदें।

SHRI GOVINDA MENON: There are several employees in each of these institutions and I do not know when each one of them were appointed. It may be that some were recruited in 1957, some in 1967 and some later. What am I to say?

SHRI INDRAJIT GUPTA: Some of them were found guilty and reinstated again.

ग्रिक्ति मारतीय स्टेशन मास्टर संघ द्वारा पारित संकल्प

#483. श्री शारवात्म्य : श्री यज्ञ वत्त शर्मा : श्री बृज भूषण साल : श्री सुरज मान : श्री रामगोपाल शालवासे :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का घ्यान ग्रांखल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ की कार्यकारिगी द्वारा मई, 1969 में दिल्ली में हुई ग्रपनी बैठकों में तथा अगस्त, 1969 में जयपुर अधिवेशन में पारित किये गए संकल्पों की ग्रीर दिलाया गया है; ग्रीर
- (स) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रैलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी): (क) जी हां। मालूम हुआ है कि इम एसोसिएशन ने दिल्ली ग्रीर खयपुर में कमशः मई, 1969 ग्रीर ग्रगस्त, 1969 को कुछ संकल्प पारित किये थे।

(ख) संघ की मांगों पर सरकार की प्रति-िया का स्वव्योकरण सदन में पहले हैं। किया जा चुका है कि सरकार द्वारा इन सभीं मांगों की जांच की गयी है, लेकिन सिवाय इसके कि एकीकृत पदोन्नति सरिण का प्रदेन रेल प्रशा-सनों के परामशं से विचाराधीन है, उनकी किसी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन कर्मचारियों को राहत देने का प्रवन भी विचाराधीन है, जो प्रपने वेननमान के प्रधिक-तम पर पहंच चुके हैं।

जहां तक वेतनमानों में सशोधन की मांगों का सम्बन्ध है. वेतन आयोग बैठाने के बारे में सरकार श्रमकों पर राष्ट्रीय आयोग की सिफा-दिशों को पहले ही सिद्धांत रूप में स्वीकार कर चुनी है धीर जब ग्रीर जैसे ही केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग बनाया जायेगा, स्टेशन मास्टरों के मामले उर भी पर्याप्त रूप से विचार किया जायेगा।

भी शारदा नन्द : भ्रष्ट्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि भ्राज देश में 27 हजार स्टेशन मास्टर काम कर रहें हैं भीर स्टेशन मास्टरों का काम स्टेशन का सुपरिवजन करना रहता है तो मैं यह जानना चाहना हूँ कि क्या सरकार को यह पता है कि बहुत से स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों का जो वेतन है उससे कही अधिक वेतन गुड्स क्लक भीर दूसरे लोगों का है तो इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार कीन सा पग उठाने जा रही है ?

दूसरी बात — जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि सरकार एक आयोग बनाने जा रही है और उसके अधीन इन सब बातों को रहेगी, तो मैं यह जानना चाहता है कि क्या सरकार रेलवे के लिए एक बेतन आयोग अलग से बनाने के प्रकृत पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्या कठिनाई है ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON): Since a Pay Commission is being appointed, I do not think it is necessary to have a separate Pay Commission because the Railways also is a part of the Central Government. But if there is any difficulty for the Pay Commission for the general employees of the Central Government looking into this matter, this suggestion will be kept in view.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What about the first question?

श्री शारवा नग्व: मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार को यह पता है कि प्रधि-कांश स्टेशन मास्टर भूख हड़ताल पर हैं? यदि हां, तो यह भूख हड़ताल कोई उग्र रूप धारए। न करे, इसके लिए सरकार स्टेशन मास्टर संघ के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे विवार-विमर्श करने के लिए तैयार हैं?

SHRI GOVINDA MENON: The

Government will give the most sympathetic consideration to the case of station masters.

श्री वज सबरा लाल : ग्रह्यक्ष महोदय, स्टे-शक म स्टरों की जो डयटी और रेस्पांसिबिलिटी है वह बहुत ज्यादा है, इसको हर ब्रादमी मानता है। इसको महेनजर रखते हुए यह जो रिपोर्ट अभी आई है जिसमें बताया है कि जो ऐक्सी-डेंट्स होते हैं उनका मेन कारणाय्ह भी हैं कि ह्यामन नेग्लिजेंस यानी स्टाफ श्रोवरवक्ड रहने से यह ऐक्सीडेंटस हम्राकरते है, यह भी वन श्राफ दि काजेज श्राफ ऐक्सीडेंटस होता है जिसमें स्टेशन मास्टरों को कभी-कभी दो-दो भीर तीन-तीन ब्रादमियों का काम करना पडता है, जो रिलीविंग वाले हैं वह नहीं पहंचते हैं जिसकी वजह से यह ऐक्सीडेंटस का एक रीजन बन जाता है, तो मैं जानना चारंगा कि ग्राइंदा रैलवे ऐक्सीडेंटस को कम करने के लिए जो रिलीविंग स्टाफ है वह ग्रालिएस्ट ग्रापारचनिटी ग्रीर टाइम पर देने की कृश करेंगे ताकि उनको सुविधा पहुंचे ?

साय ही इनकी जो डिमांड हैं कि इनके सेफ्टी मेजसं का कोई इन्तजाम नहीं है, कई स्टेशन भास्टर लूटे जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कोई विशेष कार्यवाही की है ? ग्रगर नहीं तो उसको क्यों नहीं कर रहे हैं ?

SHRI GOVINDA MENON: These suggestions for the better conditions of working on the part of station masters will be sympathetically considered.

श्री सरज मान: क्या इन स्टेशन मास्टरों का जो डिमांड आई है उसमें एक यह भी है कि रेलवे के गार्ड ऊर्ज ग्रेड के स्टेशनमास्टर बन सकते हैं लेकिन स्टेशन मास्टर ऊर्ज ग्रेड के गार्ड नहीं बन सकते ? यदि हां, तो इस एना-मली को दूर करने के निए सरकार कब तक पग उठायेगी ?

दूसरा एक छोटां सासवाल है कि एसें-शियल सर्विसेज स्टेशन मास्टसंकी सर्विसेज को मानवे हैं तो उनको भी दूसरे एसेंशियल ग्रॉब- सेज की कैटेगरों के मुता बिक रेन्ट फी क्वार्टर देन की बात सोचेंगे?

SHRI GOVINDA MENON: One of the complaints of station masters is that guards are promoted as station masters and one of the complaints of guards is that they get an opportunity for promotion only that way. All these things will, certainly, be considered by the Pay Commission and we will put forward these difficulties of our staff before the Pay Commission.

SHRI SURAJ BHAN: What about rent-free quarters?

SHRI GOVINDA MENON: Including that. That is also part of pay.

श्री रामावतार शास्त्री: ग्रह्यक्ष महोदय, रेलवे के स्टेशन मास्टरों का सवाल बड़ा बीहड है, यह हगामा बहत दिनों से हो रहा है। उनके जयपुर श्रधिवेशन में. जो 23 और 24 को अगस्त को हआ। और जहां माननीय अटल बिहारी बाजपेयी भी उमस्थित थे ग्रीर मैं भी उपस्थित था. उन लोगों ने तय किया है कि उनके वेतनमान ग्रीर लीव रिजर्वके सवालों पर यदि सरकार ने सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया तो वे शायद पहली जनवरी से कोई ग्रान्दोलन करने का विचार रखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उनकी एमोसियशन के लोगों से बातचीत करके कोई रास्ता निकालेगी ताकि स्टेशन मास्टरों की जो सम्भावित ग्रान्दोलन होने वाले हैं, उसको रोका जासके ग्रीर उनके ग्रसन्तोष को दर कियाजासके ?

SHRI GOVINDA MENON: I understand that my respected colleague in Parliament, Mr. Atal Bihari Vajpayee, is the President of this Association. I will be very happy to talk with him on all these questions.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI:
In view of the fact that the Station Masters
have been having grievances for a long time
and have been clamouring for redressing
their grievances and that no steps have been

taken to do that and, as the hon. Minister stated, that the Pay Commission will go into the details of their pay-scales and other things, may I request the hon. Railway Minister to assure the House that some interim measures will be taken in the meanwhile to remove some of their grievances that are legistimate and which can be removed immediately, affecting their services, without which they are not able to put in their service to the satisfaction of the authorities? Will the hon. Minister give that assurance?

SHRI GOVINDA MENON: Certain limited matters are being considered and a decision will be taken on those matters even before the Pay Commission begins to function.

श्री राम चरण: स्टेशन मास्टरों श्रीर एस्सिटेंट स्टेशन मास्टरों पर झाज जितना लोड-श्राफ-वर्क है स्वास तौर पर ट्रेनो की संख्या बढ़ जाने से. उस ट्रिटि से उनकी जिश्मे-दारी बहुत बढ़ती जा रही है। झाज से 10 साल पहले उनके पास जितना काम था, उससे तीन गुना अधिक काम आज उनको करना पड़ रहा है। वया इस्टेरिम पै कमीशन सैट-प्रप करने से पहले सरकार उनको कोई इस्टेरिम रिलीफ देगी?

MR. SPEAKER: It is the same question.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He will sympathetically consider.

SHRI J. M. BISWAS: Due to the adamant attitude on the part of the ex-Railway Minister, Dr. Ram Subhag Singh, the railwaymen, particularly, the Station Masters, who took part in the last strike of September 19, 1968, were subjected to a great harassment. Still the penal measures are being taken against them. I want to know from the present Railway Minister whether he is going to look into those cases sympathetically and whether he is going to condone the break in service and other penal measures inflicted under the instructions of the ex-Railway Minister, Dr. Ram Subhag Singh.

SHRI GOVINDA MENON: That is a separate question?

SHRI J. M. BISWAS: He can answer it. It is a very relevant question. Why do you allow him to evade the reply?

MR. SPEAKER: Do you want him to comment on his predecessor? I don't think you do want. You ask a straight question.

SHRI J. M BISWAS: The fact remains that many of the railwaymen have been victimised.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Without making any comment on his predec ssor, the present Railway Minister can say that all those who have been removed from service for participating in the September 1968 strike will be taken back.

MR. SPEAKER: I think you have adopted a good role of correcting the question.

SHRI GOVINDA MENON: To the best of my knowledge—I speak subject to correction—all of them have been taken back.

SHRI J. M. BISWAS: Not all.

SHRI GOVINDA MENON: That is why I said 'subject to correction'. If there are any cases remaining, they will certainly be looked into.

भी हुकम बन्द कछ वाय : ग्रध्यक्ष महोदय, रैलवे कर्मचारियों की नाना-प्रकार को समस्याएं हैं तथा इनकी विभिन्न कैंटेगरीज़ हैं। क्या सरकार इनके लिए ग्रलग से वेज-बोर्ड बनाने के लिए तैयार है नथा उन्हें भी बोनम मिले— क्या ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी: जी नहीं।

Agro-Based Industries in Andaman and Nicobar Islands

*484. SHRI K. HALDER: SHRI BHAGABAN DAS: SHRI GANESH GHOSH SHRI BADRUDDUJA:

SHRI JYOTIRMOY BASU:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Andaman and Nicobar Islands abound in natural resources:
- (b) if so, the resources available and tapped so far : and
- (c) the steps taken to develop the agrobased industrial in these islands?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOP-MENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BHANU PRAKASH SINGH): (a) Yes, Sir,

(b) and (c). A statement is placed on the Table of the Sabha. [Placed in Library See. No. LT—2301/69]

SHRI K. HALDER: The refugee problem in our country is a great problem. In fact the influx of refugees from East Pakıstan is gradually increasing. There is a great scope in Andaman and Nicobar islands to rehabilitate these refugees. Why is the Government lagging far behind the demand of the refugees?

SHRI BHANU PRAKASH SINGH: Since 1966 a detailed report has been prepared and regarding the problem of rehabilitation, the Government have already rehabilitated refugee families in various islands and they are about 646 families of which the repatriates from Burma were 37, D. Ps-540 and ex-Servicemen-69. They have already been rehabilitated.

SHRI K. HALDER: From the statement it is revealed that there is great scope for rehabilitating these refugees in the Andaman and Nicobar islands. But cattle is a problem in the islands. If the refugees are not getting cattle due to shortage of cattle, will the Government take steps to provide them with cattle and other agricultural implements so that the refugees can be rehabilitated soon.

SHRI BHANU PRAKASH SINGH:
There are no cattle in Andaman/Nicobar islands. We are trying to take cattle there.
We have already acquired a jetty for taking